POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2022/अंक 03

मासिक प्रेषण दि. 8 मार्च, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 मार्च, 2022 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट प्रस्तुत किया गया। भारत की स्वतंत्रता का यह 75वां वर्ष है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल के बजट में अगले 25 वर्षों के विकास का खाका भी सामने रखा है। माना जा रहा है, यह देश को आत्मनिर्भर व पूरी तरह सम्पन्न बनाने की दूरगामी सोच है, जो आगे जाकर एक 'मील का पत्थर' साबित होगी।

बजट में बुनियादी ढांचागत विकास को मजबूती देने के लिए पीएम गति शक्ति योजना, स्वास्थ्य सेवाओं में यूनिक हैल्थ आइडेंटिटी-अर्थात हर नागरिक की सेहत का लेखा-जोखा रखने और कृषि क्षेत्र को ग्रोथ का इंजन मानते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं सम्मिलित है। इन निवेशों से कितने स्थाई रोजगार बन सकेंगे, इसका समय-समय पर आकलन जरूरी है।

इसके अलावा बजट में ई-शिक्षा का ढांचा तैयार कर शिक्षा को विश्वस्तरीय, गुणवत्ता पूर्ण और रोजगारपरक बनाने एवं अनुसंधान पर जोर देने, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को गांरटी ऋण का बूस्टर डोज देकर प्रोत्साहित करने जैसी कई घोषणाएं बजट में शामिल है। हालांकि यह निर्णय सराहनीय है, परन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए काफी नहीं हैं। उन पर लागू होने वाले नियम कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन करके ही उन्हें बढ़ावा दिया जा सकता है।

मेरा मानना रहा है, बजट घोषणाओं को वास्तविक रूप से धरातल पर उतारने के लिए प्रशासनिक इच्छाशक्ति का होना बेहद जरूरी है। इसके लिए प्रशासनिक सुधार आवश्यक है। जनता का पैसा जो राजकोष में आता है वह बेवजह खर्च नहीं हो, यह सुशासन का मूल मंत्र होना चाहिए।

किसानों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

वित्तमंत्री ने बजट में खेती किसानी से जुड़े कामों के लिए 1,51,521 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। खेती की नई तकनीक से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्यों के अधीन आने वाले कृषि विश्वविद्यालयों में सिलेबस बदलने के लिए कहा जाएगा। इसमें कृषि से जुड़े नए कोर्स शामिल होंगे। नई तकनीक से तैयार आधुनिक खेती एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ने 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज उत्पादों की राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिग पर जोर दिया जाएगा। कृषि से संबंधित कई नए रोजगार स्थापित होंगे और किसानों को उनसे लाभान्वित किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए बजट में 12,954 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने, एमएसएमई के लिए ईसीएलजी योजना को 50 हजार करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ मार्च 2023 तक बढ़ाना बेहतर कदम माना जा रहा है। एमएसपी योजना के तहत गेहूं और धान किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधे भुगतान की घोषणा की गई है। बजट में करीब 68,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि और 15,500 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना के लिए निर्धारित हैं। 'किसान ड्रोन' से जमीन के रिकॉर्ड व कीटनाशक के छिड़काव जैसे कई काम होंगे।

ऑनलाइन मिलेगा सेहत का लेखा-जोखा

वित्तमंत्री ने बजट में 86,606 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया है। इस बार खास बात यह है कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल और स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया गया है। मानना यह रहा है कि कोरोना महामारी से लोगों का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा है। सरकार डिजिटल प्लेटफार्म लाएगी, यानी स्वास्थ्य से जुड़ी कई जानकारियां ऑनलाइन मिलेंगी। इसमें हर नागरिक की यूनिक हैल्थ आइडेंटिटी होगी, अर्थात आपकी सेहत का लेखा-जोखा होगा।

देश में 75 हजार नए ग्रामीण हैल्थ सेंटर और खोले जाएंगे। सभी जिलों में जांच केंद्र और 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे। बजट में नई बीमारियों पर भी ध्यान दिया गया है। प्राइमरी लेवल से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं पर नजर रखी गई है। नई बीमारियों पर जो खर्च होगा वह नेशनल हैल्थ मिशन से अलग हट कर होगा। बजट में 10 हजार करोड़ रुपए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए आवंटित है। अमृत शहरों में स्वच्छता के लिए करीब 2 लाख 80 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर अगले 5 सालों में एक लाख 41 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। दो हजार करोड़ रुपए सिर्फ स्वच्छ हवा के लिए खर्च किए जाएंगे।

'ग्राम गदर ग्रामीण' पत्रकारिता पुरस्कार, 2021

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 40 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ठ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2021 का विषय जिस पर उत्कृष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही है, वह है:

'विकास में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। ● टेलीफोन/मोबाइल नम्बर
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2021 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

<u>प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2022 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।</u>

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 (राजस्थान), फोन: 0141-2282821, फैक्स: 0141-2282485, 4015395

ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाईट: www.cuts-international.org

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को दी अहमियत

बजट में 1,04,278 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा मद में रखा गया है। कोविड महामारी की वजह से छात्रों की पढ़ाई पर काफी असर पड़ा है। इसे देखते हुए डिजिटल शिक्षा को ज्यादा अहमियत दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में 39,553 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उच्च शिक्षा के लिए 40,828 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। बजट में पीएम ई-विद्या योजना के तहत वन क्लास - वन टीवी चैनल को 12 की जगह 200 टीवी चैनल्स पर शुरू करने की घोषणा की गई है।

कक्षा एक से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट करते हुए पूरक पढ़ाई कराई जाएगी। सभी भाषाओं में मजबूत ई-कंटेंट विकसित किया जाएगा। जो कि इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि से संचालित किया जा सकेगा। द्रोण शक्ति योजना के तहत स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। छात्रों में क्रिएटिव स्किल्स बढ़ाने के लिए वर्ष 2022-23 में साइंस और मैथ्स की 750 वर्चुअल लैब्स और 75 स्किल ई-लैब्स खोली जाएंगी। विद्यार्थियों को घर बैठे विश्वस्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय बनेगा, जो भारतीय भाषाओं और आइसीटी फॉर्मेट में शिक्षा प्रदान करेगा।

बाल विकास एवं महिलाओं पर फोकस

महिला व बाल विकास मंत्रालय के लिए बजट में 25,172 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जबकि पिछले साल इस मद में 23,200 करोड़ रुपए दिए गए थे। वित्तमंत्री ने कहा है कि सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। इस बार बजट में बच्चों व महिलाओं के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की गई है।

इन तीन योजनाओं के तहत मिशन शक्ति के लिए 5,806 करोड़ रुपए, मिशन वात्सल्य के लिए 1,472 करोड़ रुपए और सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 को नया रूप दिया जा रहा है। कुपोषण को दूर करने एवं बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए दो लाख आंगनबाड़ियों का सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन होगा। इससे बच्चों को प्रारंभिक विकास के साथ उन्नत परिवेश मिलेगा।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के मकसद से महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। शहरी महिलाओं और कॉरपोरेट महिलाओं के लिए कोई अतिरिक्त बड़ी घोषणा बजट में नहीं की गई है।

ग्रामीण विकास पर रखी खास नजर

गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं के लिए बजट में हाथ खोलकर 2,06,293 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 48 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में है। इस योजना के तहत 80 लाख आवासों का निर्माण चिन्हित हितग्राहियों के लिए होगा। मनरेगा सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाली योजनाओं पर 1,35,944 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर खास फोकस है।

इस योजना पर 19 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्तमंत्री का कहना है कि इससे लोग नरेगा की तरह निर्माण काम से जुड़े रहेंगे, जिससे उन्हें सीधा एवं स्थाई रोजगार मिल सकेगा। बजट में इस बार ई-पंचायत से गांवों को जोड़ने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। देश की सभी 2.52 लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने का काम किया जाएगा। ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए गांवों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम तेजी से होगा।

अलग-अलग तरीकों से पनपेंगे रोजगार

बजट में अलग-अलग तरीकों में ढेरों नौकरियों के सृजन की घोषणा की गई है। अकेले मेक इन इंडिया के तहत अगले पांच सालों में 60 लाख और आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। इस घोषणा से युवाओं में आत्मबल बढ़ेगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (जीसीटीएमएसई) योजना के तहत दो लाख करोड़ रुपए का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को अतिरिक्त कर्ज का प्रावधान है।

एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ की गारंटी लिमिट का दायरा बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए करने का फायदा भी कोरोना की मार से डूबते उद्योगों को मिलेगा। रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए ई-कौशल विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी के निवेश को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किए जाने का प्रस्ताव भी बजट में है। माना जा रहा है कि निवेश बढ़ने से लोगों को नये रोजगार मिल सकेंगे।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022

जैसा कि विदित है 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' प्रति वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय 'फेयर डिजिटल फाइनेंस' है, जो डिजिटल वित्तीय सेवाओं और वित्तीय प्रौद्योगिकी व उनके परिवर्तनों से उपजे जोखिम के विरूद्ध एक विश्वव्यापी उपभोक्ता आंदोलन होगा।

जैसा कि हम जानते है कि डिजिटल वित्तीय सेवाओं और वित्तीय प्रौद्यागिकी ने दुनिया में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। हालांकि इससे नए उपभोक्ताओं के लिए नए जोखिम उभर कर सामने आ रहे हैं। वैश्विक उपभोक्ता आंदोलन के रूप में, हम सभी के लिए 'फेयर डिजिटल फाइनेंस' को बढ़ावा देने और उपभोक्ता के अधिकारों के महत्व को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अतः सभी उपभोक्ता संस्थाएं इस अवसर पर अपने-अपने क्षेत्र में उक्त विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर जनसाधारण को जागृत और सचेत करें। कृपया कार्यक्रम की रिपोर्ट 'ग्राम गदर' को अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

आधारभूत ढांचा होगा और ज्यादा मजबूत

बजट में आधारभूत ढांचे की नींव को और मजबूत करने के लिए सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, सौर व पवन ऊर्जा संबंधी उपक्रमों आदि का बजटीय आवंटन 35.4 फीसदी बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। बजट में आवास और शहरी विकास के लिए 76,549 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

गरीबों व जरूरतमंदों के लिए 80 लाख सस्ते आवास बनाने के लिए 48 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आधारभूत विकास के लिए सार्वजनिक परिवहन में सुधार के कदम उठाए गए है। इस बार 19 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए निर्धारित है।

एक्सप्रेसवे के लिए गति शक्ति प्लान अस्तित्व में आएगा। नेशनल हाईवे का दायरा 25 हजार किमी बढ़ेगा। इससे त्वरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। अगले तीन सालों में रेलवे नेटवर्क बढ़ाते हुए 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने और रेलवे स्टेशनों के विकास की बात की गई है। बड़ी बात यह है कि राज्यों से बेहतर नगर नियोजन के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी।

हर घर नल से जल योजना के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जाएगा। सौर ऊर्जा और उससे जुड़े उपकरणों के लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में है। वित्तमंत्री का मानना है कि बुनियादी ढांचे के विकास से शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा।

'ग्राम गदर' हिन्दी मासिक

फार्म-4 (नियम 8)

'ग्राम गदर हिन्दी मासिक' के स्वामित्व का विवरण और अन्य विशिष्टियाँ जिनका प्रकाशन प्रत्येक वर्ष अन्तिम प्रकाशन दिवस पर करना होता है, निम्नवत है-

1.	प्रकाशन का स्थान	-	जयपुर
2.	प्रकाशन अवधि	-	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	-	भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
4.	प्रकाशक का नाम	-	प्रदीप सिंह महता
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
	पता	-	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
5.	सम्पादक का नाम	-	प्रदीप सिंह महता
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
	पता	-	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा समस्त पूँजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हों।	-	एक मात्र स्वामी प्रदीप सिंह महता

मैं प्रदीप सिंह महता एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

प्रदीप सिंह महता
प्रकाशक के हस्ताक्षर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स', जयपुर